

संविधान का मूल



संविधान के मूल तत्व



मौलिक अधिकार

ये अधिकार इस अर्थ में मौलिक हैं कि देश में विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून को अशक्त और शून्य घोषित किया जाएगा यदि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है।

यदि इनमें से किसी भी अधिकार का हनन किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का हकदार है। हालाँकि, अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और आपातकाल के दौरान इस पर अंकुश लगाया जा सकता है।

भाग-3 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद-12-35)

- मौलिक अधिकारों को भारत के मैगना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है।
- यह अवधारणा अमेरिका के अधिकारों के विधेयक से ली गई है। अधिकारों के शुरुआती ज्ञात प्रमाण प्राचीन भारत, ईरान आदि में भी मौजूद थे।
- मौलिक अधिकारों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित हैं, जो कि देश का मौलिक कानून है। वे इस अर्थ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए सबसे आवश्यक हैं।
- मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, हालांकि, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद, संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था और अब केवल छह मौलिक अधिकार शेष हैं।

मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित हैं-

A. 12- राज्य की परिभाषा

B. 13- भाग-3 या मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून

मौलिक अधिकारों का पृथक्करण निम्नानुसार है

C. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- (a) कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा (अनुच्छेद 14)।
- (b) धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)।
- (c) सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)।
- (d) अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसकी परंपरा का निषेध (अनुच्छेद 17)।
- (e) सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन (अनुच्छेद 18)।

D. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

(a) स्वतंत्रता से संबंधित निम्न छह अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19):

- i. भाषण और अभिव्यक्ति
- ii. सभा करना
- iii. संघ बनाना
- iv. आंदोलन करना
- v. निवास करना और
- vi. व्यवसाय करना

(b) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)।

(c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।

(d) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)।

(e) कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 22)।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

- (a) मानव दुर्व्यापार और मजबूर श्रम पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 23)।
- (b) कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 24)।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- (a) अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)।
- (b) धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
- (c) किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)।
- (d) कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

- (a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29)।
- (b) अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार (अनुच्छेद 30)।

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) - संविधान का हृदय और आत्मा।

निम्न अधिकारों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार

- (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) निषेधाज्ञा, (iv) अधिकार पृच्छा, और (v) उत्प्रेषण रिट (अनुच्छेद 32)।

अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है

अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के समाधान के लिए आवश्यक कानून से संबंधित है।

मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं - 15, 16, 19, 29 और 30।

मौलिक अधिकार जो नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों, दोनों को उपलब्ध हैं - 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28।

भाग-4 मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद -51 A)

वे नागरिकों के लिए 11 दिशानिर्देशों का एक समूह हैं।

मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था।

- यह अवधारणा पूर्व सोवियत संविधान से लिया गया है और अब रूस के पास भी ये नहीं हैं। संभवतः केवल जापान ही एक ऐसा प्रमुख देश है जिसके पास मौलिक कर्तव्यों पर एक विशेष अध्याय है।
- 1976 में, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
- इन्हें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। इसने आर्थिक दंड के साथ-साथ 8 मौलिक कर्तव्यों की भी सिफारिश की थी। हालांकि, सरकार ने दंडात्मक भाग का स्वागत नहीं किया।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के आधार पर एक नया भाग- 4A, एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। 51A में दस कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में ग्यारह कर्तव्य हैं।
- 11 वें मौलिक कर्तव्य को 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।

मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नानुसार है:

- (a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना;
- (b) स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और पालन करना;
- (c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना;
- (d) देश की रक्षा करना और ऐसा करने का आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना;

- (e) भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार का त्याग करना;
- (f) देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना;
- (g) वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और जीवित प्राणियों के लिए दया करना;
- (h) वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करना;
- (i) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को रोकना;
- (j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़े; तथा
- (k) अपने बच्चे को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

भारत की संसद (अनुच्छेद 79-122)

संसद का संगठन

संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं।

लोकसभा निचला सदन (प्रथम चैंबर या लोकप्रिय सदन) है और राज्य सभा उच्च सदन (द्वितीय चैंबर या बड़ा सदन) है।

राज्यसभा की संरचना

- राज्य सभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं।
- वर्तमान में, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए हैं।
- संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन से संबंधित है।

- राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं।

टिप्पणी - 87वें संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर ज्ञात जनसंख्या।

लोकसभा की संरचना

- लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे और 2 सदस्य एंग्लो-भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं।
- वर्तमान में, लोकसभा में 545 सदस्य हैं।
- लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि सीधे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
- संसद के दोनों सदनों की अवधि
- राज्य सभा एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि, इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य किसी भी समय पुनः निर्वाचन और फिर से नामांकन के लिए पात्र हैं।
- राज्यसभा के विपरीत, लोकसभा एक सतत चैम्बर नहीं है। आम चुनावों के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से इसका सामान्य कार्यकाल पांच साल है, जिसके बाद यह स्वचालित रूप से भंग हो जाती है।

पात्रता

- भारत का नागरिक।
- न्यूनतम आयु - राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष।
- उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए। (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार)।

लोकसभा अध्यक्ष (सभापति)

- अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाता है (उसकी पहली बैठक के बाद, जितनी जल्दी हो सके)। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

- अध्यक्ष उप-सभापति को अपना इस्तीफा प्रदान करता है और उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, हालांकि, केवल उसे 14 दिन का नोटिस देने के बाद।
- वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऐसे सदन को राष्ट्रपति द्वारा एक विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निपटारे के लिए बुलाया जाता है।
- वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस सवाल पर उसका निर्णय अंतिम है।
- वह पहली बार में वोट नहीं कर सकते, हालांकि बराबर रहने (टाई) की स्थिति में वोट कर सकते हैं। जब उसका निष्कासन प्रस्ताव विचाराधीन है, तो वह भाग ले सकता है और कार्यवाही में बोल सकता है और मतदान भी कर सकता है लेकिन टाई के मामले में नहीं। वह उस मामले में अध्यक्षता नहीं कर सकता। हालाँकि, उनकी प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है और इसे केवल तभी माना जा सकता है जब उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।
- जी. वी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे।
- लोकसभा के अब तक के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे हैं।

लोकसभा के उपाध्यक्ष

- लोकसभा अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष को भी लोकसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है।
- उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। निष्कासन प्रक्रिया स्पीकर के समान होती है और वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा प्रदान करता है।
- मदाभुशी अनंतशयानम अय्यंगार लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे।
- वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति के मामले में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

संसद के सत्र

संसद का एक 'सत्र' किसी सदन के पहली बैठक और उसके सत्रांत (या लोक सभा के मामले में विघटन) के बीच का समय होता है। किसी नए सत्र में किसी सदन के सत्रांत और उसके पुनर्सभा के बीच की समयावधि को 'अवकाश' कहा जाता है। आमतौर पर तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र सबसे लंबा और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है।

- बजट सत्र (फरवरी से मई);
- मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर); तथा
- शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)।

BASICS OF CONSTITUTION



Fundamental Rights

These rights are fundamental in the sense that any law passed by the legislature in the country would be declared as null and void if it is in contravention to the rights guaranteed by the constitution.

If any of these rights are violated, the individual affected is entitled to move the Supreme Court or High Court for the protection and enforcement of his rights. However, The rights are not absolute and can be curtailed during the emergency.

Part-3 Fundamental Rights (Article-12-35)

- Fundamental Rights have been described as the Magna Carta of India.
- The concept has been taken from the US' bill of rights. Earliest known evidence of rights was also present in ancient India, Iran etc.
- The Fundamental Rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. They are 'fundamental' also in the sense that they are the most essential for the all-round development (material, intellectual, moral and spiritual) of the individuals.
- The original constitution contained seven fundamental rights, however, after the 44th constitutional amendment act, 1978, right to property was repealed and now only six fundamental rights remain.

Following are the articles related to the fundamental rights-

A. 12- Definition of the State

B. 13- Laws inconsistent with part-3 or Fundamental Rights

Following is the segregation of the Fundamental Rights

C. Right to equality (Articles 14-18)

- (a) Equality before the law and equal protection of laws (Article 14).
- (b) Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15).
- (c) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16).
- (d) Abolition of untouchability and prohibition of its practice (Article 17).
- (e) Abolition of titles except military and academic (Article 18).

D. Right to freedom (Articles 19-22)

- (a) Protection of six rights regarding freedom of (Article 19):
 - i. Speech and Expression
 - ii. Assembly
 - iii. Association
 - iv. Movement,
 - v. Residence, and
 - vi. Profession
- (b) Protection in respect of conviction for offences (Article 20).
- (c) Protection of life and personal liberty (Article 21).

(d) Right to elementary education (Article 21A).

(e) Protection against arrest and detention in certain cases (Article 22).

Right against exploitation (Articles 23-24)

(a) Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23).

(b) Prohibition of employment of children in factories, etc. (Article 24).

Right to freedom of religion (Article 25-28)

(a) Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (Article 25).

(b) Freedom to manage religious affairs (Article 26).

(c) Freedom from payment of taxes for promotion of any religion (Article 27).

(d) Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions (Article 28).

Cultural And Educational Rights (Articles 29-30)

(a) Protection of language, script and culture of minorities (Article 29).

(b) Right of minorities to establish and administer educational institutions (Article 30).

Right to constitutional remedies (Article 32)- Heart and Soul of the Constitution.

Right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights including the writs of

(i) habeas corpus, (ii) mandamus, (iii) prohibition, (iv) certiorari, and (v) quo warranto (Article 32).

Article 33 deals with the power of Parliament to modify the fundamental rights.

Article 34 deals with Martial Law

Article 35 deals with legislation required to deal with fundamental rights

Fundamental Rights which are available to only citizens - 15, 16, 19, 29 and 30.

Fundamental Rights those are available to both citizens as well as non-citizens - 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28.

Part-4 Fundamental Duties (Article-51A)

They are a set of 11 guidelines to the citizens.

The original constitution did not mention about the FDs.

- The idea has been taken from the former Soviet Constitution and now even Russia does not have them. Probably only Japan is one such major country which has an exclusive chapter on fundamental duties.
- In 1976, the fundamental duties of citizens were added in the Constitution. In 2002, one more Fundamental Duty was added.
- They were added on the recommendations of the Swaran Singh Committee which was constituted by Indira Gandhi in 1975. It recommended only 8 fundamental duties than with pecuniary punishments as well. However, the government did not welcome the punishments part.
- A new part - 4A, A NEW ARTICLE 51A was added by virtue of 42nd constitutional amendment act, 1976. Ten duties were added to 51A. Presently there are eleven duties.
- The 11th Fundamental Duty was added by 86th amendment act, 2002.

Following is the list of FDs:

(a) To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

- (b) To cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom;
- (c) To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) To defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) To value and preserve the rich heritage of the country's composite culture;
- (g) To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures;
- (h) To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) To safeguard public property and to abjure violence;
- (j) To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement; and
- (k) To provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.

Parliament of India (Articles 79-122)

Organization of the Parliament

The Parliament consists of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha.

Lok Sabha is the Lower House (First Chamber or Popular House) and Rajya Sabha is the Upper House (Second Chamber or House of Elders).

Composition of Rajya Sabha

- The maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at 250, out of which, 238 are to be the representatives of the states and union territories (elected indirectly) and 12 are nominated by the president.
- At present, the Rajya Sabha has 245 members. Of these, 229 members represent the states, 4 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president.
- The Fourth Schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories.
- The representatives of states in the Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assemblies. The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population.

NOTE - Population as ascertained on the basis of 2001 census as per 87th Amendment Act, 2003.

Composition of Lok Sabha

- The maximum strength of the Lok Sabha is fixed at 552. Out of this, 530 members are to be the representatives of the states, 20 members are to be the representatives of the union territories and 2 members may be nominated by the president from the Anglo-Indian community.
- At present, the Lok Sabha has 545 members.
- The representatives of states in the Lok Sabha are directly elected by the people from their respective constituencies.
- The voting age was reduced from 21 to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act, 1988.
- Duration of the two Houses of Parliament
- The Rajya Sabha is a permanent body and not subject to dissolution. However, one-third of its members retire every second year. The retiring members are eligible for re-election and re-nomination any number of times.

- Unlike the Rajya Sabha, the Lok Sabha is not a continuing chamber. Its normal term is five years from the date of its first meeting after the general elections, after which it automatically dissolves.

Eligibility

- (a) Citizen of India.
- (b) Minimum age - 30 years in Rajya Sabha and 25 years in Lok Sabha.
- (c) He must possess other qualifications prescribed by Parliament. (Hence, the Representation of People Act, 1951).

Speaker of the Lok Sabha

- The Speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members (as soon as may be, after its first sitting). The date of election of the Speaker is fixed by the President.
- The Speaker offers his resignation to the Deputy Speaker and he can be removed by a resolution passed by a majority of members of Lok Sabha, however, only after giving him a 14-day notice.
- He presides over a joint sitting of the two Houses of Parliament. Such a sitting is summoned by the President to settle a deadlock between the two Houses on a bill.
- He decides whether a bill is a money bill or not and his decision on this question is final.
- He can't vote in the first instance, though can vote in the event of a tie. When his removal motion is under consideration, he can take part and speak in the proceedings and can vote as well but not in the case of a tie. He can't preside in that case. However, his motion can be passed by an absolute majority only and can be considered only if it has the support of at least 50 members.
- G.V Mavalankar was the first Speaker of Lok Sabha.
- The longest serving Speaker of Lok Sabha so far has been Balram Jakhar.

Deputy Speaker of the Lok Sabha

- Like the Speaker, the Deputy Speaker is also elected by the Lok Sabha itself from amongst its members.
- The date of election of the Deputy Speaker is fixed by the Speaker. The removal process is the same as that of the speaker and he offers his resignation to the Speaker of the Lok Sabha.
- Madabhushi Ananthasayanam Ayyangar was the first Deputy Speaker of Lok Sabha.
- He presides over the joint sitting in case of absence of the Speaker.

Sessions of Parliament

A 'session' of Parliament is the period spanning between the first sitting of a House and its prorogation (or dissolution in the case of the Lok Sabha). The time period between the prorogation of a House and its reassembly in a new session is called 'Recess'. There are usually three sessions. The budget session is the longest and winter is the shortest.

- The Budget Session (February to May);
- The Monsoon Session (July to September); and
- The Winter Session (November to December).